भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †4469
19 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

मध्य प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार

†4469. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहानः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'ऑपरेशन ग्रीन्स' योजना, जो शुरू में केवल टीओपी (टमाटर, प्याज, आलू) फसलों तक सीमित थी, उसे सभी नाशवान कृषि उपज तक विस्तारित करने के संबंध में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है और मध्य प्रदेश सहित देश में उक्त योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश में उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और उद्यमियों की कुल संख्या का जिला-वार और विशेषकर रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (संख्या 24) के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त योजना के माध्यम से उपरोक्त लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में किसानों की आय में वृद्धि और फसल की बर्बादी में कमी के संबंध में कोई प्रभाव संबंधी मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): केंद्रीय बजट वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में, "ऑपरेशन फ्लड" की तर्ज पर 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ"ऑपरेशन ग्रीन्स" योजना की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों, कृषि-लाजिस्टिक , प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा था। यह योजना दो घटकों के साथ प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी: (i) अल्पकालिक: मूल्य स्थिरीकरण उपाय (परिवहन और भंडारण - 50% सब्सिडी) और (ii) दीर्घकालिक: मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं। माननीय वित्त मंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा के अंतर्गत , ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत अल्पकालिक उपायों का दायरा 11.06.2020 से टीओपी से (टीओटीएएल) तक विस्तारित किया गया था। इसके अलावा, केंद्रीय बजट वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में, दीर्घकालिक रणनीति यानी एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं और ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत स्टैंडअलोन फसलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं का दायरा, जो मूल रूप से टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) फसलों पर लागू था, को बढ़ाकर 22 नाशवान फसलों तक कर दिया गया। दीर्घकालिक अंतःक्षेप घटक के अंतर्गत , मंत्रालय ने देश में 41 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इनमें से एक परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में स्वीकृत की गई है, जो चालू है। 41 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

(ख) एवं (ग): मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के धार जिले में एक एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना को स्वीकृति दी है। इस परियोजना से एक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को लाभ मिला है, जिसमें कुल 548 किसान शामिल हैं। हालांकि, मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी है।

*****

अनुबंध

दिनांक 19.03.2026 को उत्तर हेतु "मध्य प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या † 4469 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत स्वीकृत दीर्घकालिक अंत:क्षेप परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति निम्न प्रकार है:

स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	जारी	पूर्ण	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत सहायता अनुदान (करोड़ रुपये में)	जारी अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)
41	19	22	1901.76	451.30	286.13